शनिवार, 4 मार्च, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

संजू सैमसन CSK के लिए गेम चेंजर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'रामायण' का टीज़र रिलीज़ होते ही मचा धमाल सोशल मीडिया पर छाए रणबीर कपूर

Page-05

मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने तेल के बाद अब पानी और गैस प्लांट्स पर हमला किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी और राजनीतिक उलझनें बढ़ेंगी।

असम चुनाव में योगी की चेतावनी

घुसपैठियों को नहीं बख्शेंगे!

- **कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर घुसपैठ का आरोप**
- **योगी ने असम में एनडीए का प्रचार किया**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल 2026 को असम के बारपेटा में आयोजित एक जनसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच अंतर स्पष्ट किया। रैली में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य और देश में सुरक्षा, सुशासन और संस्कृति की रक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों — गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं — तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।योगी ने एनडीए सरकार के "दोहरे इंजन वाली सरकार" के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में असम में विकास और सुधार का नया दौर आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद राज्य की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा में विफल रही। उनका कहना था कि कांग्रेस ने घुसपैठ, हिंसा और दंगों को बढ़ावा दिया और असम की स्थानीय संस्कृति और विरासत को खतरे में डाला।इसके अलावा, उन्होंने एआईयूडीएफ पर भी निशाना साधा और कहा कि यह संगठन घुसपैठियों का समर्थन कर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि भाजपा और राजग सरकार राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान करके उसे खदेड़ दिया जाएगा और राजग किसी भी प्रकार के "लव और लैंड जिहाद" या जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगा।उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बारपेटा से अपने उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर मैदान से पहले ही भागकर चुनाव की गंभीरता को दरकिनार कर दिया है। आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए भाजपा को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम में व्यापक बदलाव हुआ है और राज्य में विकास और सुरक्षा का संतुलन सुनिश्चित किया गया है। असम विधानसभा के 126 सदस्यीय चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। योगी आदित्यनाथ की यह रैली भाजपा के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, जिसमें विकास और विरासत के एजेंडे को प्रमुखता दी गई।

रूस, चीन और फ्रांस ने जताई कड़ी आपत्ति

स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर खाड़ी देशों और वैश्विक ताकतों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरीन की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सैन्य कारवाई की अनुमति देने की मांग की गई। प्रस्ताव में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों की भूमिका को भी शामिल किया गया।हालांकि, रूस, चीन और फ्रांस ने सैन्य बल इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर सख्त आपत्ति जताई। इन देशों का कहना है कि इस तरह की भाषा टकराव को और बढ़ा सकती है और क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेल सकती है। इसके कारण प्रस्ताव फिलहाल अटका हुआ है और सुरक्षा परिषद में मतभेद उजागर हो गए हैं। यह विवाद 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब ईरान ने अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज ट्रेड को बंद कर दिया। यह मार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई, तेल और शिपिंग की कीमतें बढ़ीं और बीमा लागत भी बढ़ी। खाड़ी देशों का कहना है कि यह सिर्फ क्षेत्रीय मामला नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। वहीं, कई वैश्विक नेता सैन्य विकल्प को खतरनाक मान रहे हैं। पहले इस मार्ग से रोजाना 100-150 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर 5-7 रह गई है। भारत के कई जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन गया है।

आतिशी का राघव चड्ढा पर हमला

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की कड़ी आलोचना की। आतिशी ने आरोप लगाया कि चड्ढा राष्ट्रीय संकट के समय आम नागरिकों के सामने गंभीर समस्याओं, जैसे एलपीजी गैस की कमी, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। X पर साझा किए गए वीडियो में आतिशी ने कहा, "देश संविधान संकट और चुनाव आयोग के दुरुपयोग के बीच गुजर रहा है, लेकिन आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? जब टीएमसी और अन्य विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, आप हस्ताक्षर करने से क्यों कतराते हैं?" उन्होंने आगे कहा कि एलपीजी की कमी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित कर रही है और देशवासियों को तय करना होगा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं या लोकतंत्र के पक्ष में। इस विवाद के बीच, आप के नेता अनुराग ढांडा ने चड्ढा की ओर से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चड्ढा कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते रहे हैं। ढांडा ने यह भी कहा कि राज्यसभा में उनकी चुप्पी को हार नहीं माना जाना चाहिए और सवाल उठाया कि उन्हें बोलने से क्यों रोका गया। यह मामला पार्टी में मतभेद और नेताओं के दृष्टिकोण के अंतर को उजागर करता है, जबकि एलपीजी संकट आम जनता की चिंता का मुख्य मुद्दा

ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया

भारत समेत वैश्विक फार्मा उद्योग पर पड़ेगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ नीति में बड़ा बदलाव किया है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी ब्रांडेड दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। इसका सीधा असर उन फार्मास्युटिकल कंपनियों पर पड़ेगा, जो अपनी दवाइयां अमेरिका के बाहर उत्पादन करती हैं।नई नीति के तहत, जो कंपनियां आंशिक रूप से अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करेंगी, उन्हें 20% टैक्स देना होगा। वहीं नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों से 100% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप का दावा है कि इस फैसले से दवाइयां सस्ती होंगी और देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, ट्रंप ने स्टील, एलुमिनियम और तांबे के उत्पादन और आयात पर भी बदलाव किए हैं। 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 232 के तहत स्टील, एलुमिनियम और तांबे पर 50% शुल्क बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ मेटल्स पर टैरिफ 25% किया गया है। उन उत्पादों पर जिनमें मेटल की मात्रा 15% से कम है, टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। अब शुल्क आयातित वस्तु के मूल्य पर लगेगा, न कि केवल धातु की मात्रा पर। ट्रंप के इस फैसले के पीछे फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैक्सों को गैरकानूनी करार देने का बड़ा कारण है। इसके चलते ट्रंप सरकार को 166 अरब डॉलर वापस करना पड़ा था। नए नियम इसी नुकसान की भरपाई और अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि जेनेरिक दवाओं को इस टैरिफ से छूट दी गई है। भारत के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार में भारतीय कंपनियों का दबदबा है। इससे अल्पावधि में अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं के निर्यात को सुरक्षा कवच मिलेगा और कम लागत वाली दवाइयों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम वैश्विक फार्मा उद्योग और भारत के दवा निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जबकि अमेरिकी कंपनियों को अपनी उत्पादन रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।

राजस्थान SI परीक्षा में राहत सिर्फ एक छात्र को,

लाखों उम्मीदवारों को झटका

राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने गुरुवार को सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि केवल मूल याचिकाकर्ता, सूरज मल मीना को ही राहत दी जा सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवारों को इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। पिछला आदेश सूरज मल मीना द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था। मीना ने 5-6 अप्रैल को निर्धारित परीक्षा में भाग न ले पाने के कारण इसे कम से कम चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी। प्रारंभिक आदेश में न्यायालय ने परीक्षा को अस्थायी रूप से स्थगित करने की अनुमति दी थी, जिससे लगभग 2.21 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा देने की राह खुलती दिखाई दी थी। हालांकि, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समायोजित करना उनके लिए संभव नहीं है। इस पर विशेष पीठ ने आदेश में संशोधन करते हुए राहत केवल सूरज मल मीना तक सीमित कर दी। न्यायालय ने यह भी तर्क दिया कि मीना के अतिरिक्त किसी अन्य उम्मीदवार ने सीधे इस तरह की राहत के लिए संपर्क नहीं किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

अन्य उम्मीदवार अब भी राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं और निर्णय के आधार पर न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से

महिला आरक्षण विधेयक पर होगी जोरदार बहस

संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा, और महिला आरक्षण विधेयक पर बहस केंद्र में होगी। सरकार लोकसभा की सीटें 543 से 816 करने की योजना बना रही है। विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, जबकि सांसद उप-कोटा और राज्य विधान परिषद में लागू होने जैसे सवाल उठा रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद का बजट सत्र 16 अप्रैल से थोड़े समय के विराम के बाद पुनः शुरू होगा और सभी की निगाहें महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर टिकी हैं। सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है ताकि महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, सत्र लगभग तीन दिनों तक चलेगा और प्रस्तावित विधेयकों को सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।सरकार की योजना नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है। सरकार का मानना है कि कानून को लागू करने का समय आ गया है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वह विपक्षी दलों के संपर्क में है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को निर्धारित है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में संशोधन की इच्छा जताई। इसके जवाब में खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ बुलाकर सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा की जाए। 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव से सहमति जताई और सर्वसम्मति से कहा कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद बुलाई जानी चाहिए।इस मुद्दे ने राज्यसभा में तीखी बहस छेड़ दी है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कानून कब लाया जाए, यह तय करने का अधिकार सरकार के पास है। वहीं, कई विपक्षी सदस्य चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह ने सरकार पर इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सांसदों ने महिला आरक्षण को लेकर कई व्यापक चिंताएं भी जताईं। फौजिया खान ने पूछा कि क्या राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में भी इसी तरह का आरक्षण लागू होगा। मनोज झा ने सवाल किया कि आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए उप-कोटा होगा या नहीं। महिला आरक्षण विधेयक संसद में आने के बाद राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। इस सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा न केवल विधेयक के प्रावधानों पर बल्कि लागू होने के समय और रणनीति पर भी केंद्रित रहेगी। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है: महिलाओं के लिए संसद में सीट आरक्षित करना और देश में लैंगिक समानता के लिए कानून का मजबूत संदेश देना। विपक्ष की प्रतिक्रिया और बहस का स्वरूप इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बना देता है।सत्र के तीन दिनों में यह तय होगा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार कितनी तेजी से कदम उठाती है और विपक्षी दल इसके लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। 16 अप्रैल से शुरू होने वाला यह सत्र भारतीय संसद में महिलाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

ईरान की शक्ति का नया प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका–इज़राइल के बीच संघर्ष लगातार खतरनाक रूप ले रहा है। इस बीच ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई आईआरजीसी के एयरोस्पेस चीफ मेजर जनरल माजिद मौसमी फिर से सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों उनके मारे जाने या लापता होने की खबरें फैल चुकी थीं, लेकिन हाल ही में ईरानी स्टेट मीडिया द्वारा जारी वीडियो में मौसमी को अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का दौरा करते, सैनिकों से मिलते और ऑपरेशन की ब्रीफिंग लेते हुए देखा गया। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका, इज़राइल और खाड़ी क्षेत्र के देशों को निशाना बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के विशाल भंडार से यह संकेत मिलता है कि ईरान केवल बचाव नहीं कर रहा बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में डटा हुआ है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में मौसमी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि जंग के शुरुआती दौर में उनके न होने से एयररोस्पेस यूनिट कमजोर हुई और हुए नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मिसाइल हमलों और उनके नतीजों को लेकर गलत आंकड़े पेश करने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध समाप्ति की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान अब खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है और दावा कर रहा है कि वाशिंगटन खुद इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। रूस और अन्य वैश्विक खिलाड़ी भी इस संघर्ष पर सवाल उठा चुके हैं।

भारत ने बुर्कीना फासो को 10 लाख किलो

चावल भेजकर भविष्य की रणनीति मजबूत की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भयानक होती जा रही अमेरिका–ईरान जंग के बीच भारत ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाया है। इसी कड़ी में भारत ने अफ्रीका के देश बुर्कीना फासो को 10 लाख किलो चावल भेजा। यह कदम न केवल मानवीय मदद के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि भविष्य में आर्थिक और रणनीतिक लाभ के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुर्कीना फासो वर्तमान में अस्थिरता और प्राकृतिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हालांकि यह देश खनिज संपदा और सोने के भंडार के लिहाज से अमीर है। भारत ने संकट में फंसे इस देश को मानवीय सहायता भेजकर उसके साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। इसके बदले बुर्कीना फासो भारत को उचित मूल्य पर सोना उपलब्ध कराएगा, जिससे भारत की भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बुर्कीना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम त्रावरे ने पिछले वर्ष रूस का दौरा किया था और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके समर्थक हैं। इस तरह बुर्कीना फासो के साथ भारत का रिश्ता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत अफ्रीका के महाद्वीप को रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इसी कड़ी में उसने अफ्रीका यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया। इससे अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। पहले अंगोला ने एलपीजी गैस बेची, वहीं नाइजीरिया ने तेल की आपूर्ति की। बुर्कीना फासो और सियरा लियोन जैसी देशों के साथ भारत की यह नई रणनीति भविष्य में महाद्वीपीय संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस कदम से बुर्कीना फासो को संकट से उबरने में मदद मिलेगी, और भारत को सोने और हीरे जैसी महत्त्वपूर्ण संसाधनों में लाभ होगा। इस रणनीति के तहत भारत ने सियरा लियोन को भी 10 लाख किलो चावल भेजे हैं। सियरा लियोन दुनिया के बड़े हीरा उत्पादक देशों में शामिल है और भारत का डायमंड उद्योग इसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट में नेतृत्व बनाए रखता है।

ईरान ने मध्य आकाश में अमेरिकी एफ-35

लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को दावा किया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली ने मध्य ईरान के ऊपर एक अमेरिकी एफ-35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मार गिराया। ईरानी स्टेट चैनल प्रेस टीवी के अनुसार, यह विमान आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स की नई तैनात वायु रक्षा तकनीक द्वारा निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि विमान के टकराने और गिरने के दौरान हुए विस्फोट की वजह से पायलट के जीवित बचने की संभावना बहुत कम है। खातम अल-अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमला आईआरजीसी के लेकन-हीथ स्क्वाड्रन की आधुनिक प्रणाली से किया गया, जो अमेरिकी स्टील्थ तकनीक को चुनौती देने में सक्षम है।ईरानी मीडिया ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइल बादलों को चीरती हुई एफ-35 की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। आईआरजीसी ने इसे अपनी नई वायु रक्षा तकनीक की सफलता करार दिया।यह हमला पिछले कुछ हफ्तों में एफ-35 विमानों पर किए गए हमलों की एक कड़ी माना जा रहा है। ईरान ने पहले 19 मार्च को दावा किया था कि वह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अमेरिकी एफ-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया। लाइटनिंग 2 अमेरिका के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण युद्धक विमानों में से एक है और इसे कई देश अपने एयरफोर्स में शामिल कर चुके हैं या करने की योजना बना रहे हैं। अभी तक अमेरिकी सेना ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन ईरानी दावे और वीडियो ने वैश्विक सुरक्षा और मध्य एशिया में तनाव की स्थिति को और गहरा कर दिया है। अगर यह दावा सत्य साबित होता है, तो यह अमेरिकी वायु शक्ति और एफ-35 की रणनीतिक प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। ईरान की इस कार्रवाई ने मध्य-पूर्व में सैन्य संतुलन और अमेरिकी रणनीति पर गहरा असर डालने की संभावना बढ़ा दी है।

ईरान–इजरायल टकराव में हिज़्बुल्लाह भी युद्ध में कूदा

मिडिल ईस्ट में संघर्ष अब महायुद्ध की तरफ ?

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया का संकट अब और गहराता नजर आ रहा है, और हालात तेजी से बड़े संघर्ष की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए हैं, वहीं अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले दो से तीन हफ्तों में ईरान पर बेहद कड़े हमले किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई जारी रहेगी, तब तक वह जवाबी हमले करता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश इस युद्ध, बातचीत और युद्धविराम के चक्र को स्वीकार नहीं करेगा और हर हमले का जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी हमले का जवाब गंभीर होगा और ईरान अपनी रक्षा में पीछे नहीं हटेगा।इजरायल ने पिछले चौबीस घंटों में हिज्बुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और करीब चालीस लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने हवाई, समुद्री और जमीनी तीनों मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है, वहीं दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान भी जारी है।ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो इसका परिणाम बेहद भारी होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि कोई भी दुश्मन सैनिक जीवित नहीं बच पाएगा, जिससे संकेत मिलता है कि टकराव और बढ़ सकता है।तनाव इतना बढ़ गया है कि इराक में अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। इजरायल ने कई बार ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी। खाड़ी क्षेत्र में भी असर दिख रहा है। अबू धाबी के पास एक मिसाइल को रोकने में सफल रही, जबकि हिज्बुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए। वैश्विक स्तर पर भी इसका असर दिख रहा है। तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है, खासकर होरमुज जलडमरूमध्य के कारण। हालांकि ईरान ने फिलीपींस को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया। रूस और चीन ने स्थिति पर चिंता जताई; चीन ने युद्धविराम की अपील की, जबकि रूस ने जरूरत पड़ने पर समाधान में मदद का संकेत दिया। भारत के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ईंधन या गैस की कोई कमी नहीं है और भारतीय नौसेना तेल टैंकरों को सुरक्षित मार्ग दिलाने में सक्रिय है।

संपादक की कलम से

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की शक्ति और भविष्य का सबसे बड़ा आधार है। यह न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित करती है, बल्कि समाज और देश की तरक्की का मार्ग भी तय करती है। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज के बदलते युग की चुनौतियों के अनुरूप नहीं है। अगर हम समय रहते सुधार नहीं करेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुँच पाएगी। आज स्कूल और कॉलेज शिक्षा में कई समस्याएँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का अधूरा वातावरण, शिक्षक-संख्या की कमी और पुराने पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि को प्रभावित करते हैं। वहीं, निजी स्कूलों में संसाधनों की अधिकता होने के बावजूद शिक्षा केवल परीक्षा केंद्रित बन गई है। इससे छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और व्यावहारिक ज्ञान की कमी हो रही है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। इसे छात्रों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और समाज के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में विज्ञान, कला, तकनीकी शिक्षा और जीवन कौशल का संतुलित समावेश होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, शिक्षकों का प्रशिक्षण आधुनिक तकनीकों और शिक्षण पद्धतियों के अनुरूप होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालय और इंटरेक्टिव शिक्षण उपकरण छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान और रोचक बना सकते हैं। लेकिन इसका लाभ तभी संभव है जब डिजिटल तकनीक हर बच्चे तक पहुँचे, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। समाज और परिवार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को केवल परीक्षा के अंक तक सीमित न रखकर उनकी रुचियों और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी शामिल करना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी सिर्फ विद्या नहीं, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनें। सरकार, शिक्षक और समाज—तीनों मिलकर ही शिक्षा में सुधार के असली लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की तैयारी, कौशल और मूल्यों का संयोजन होना चाहिए। यदि हम आज सुधार के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएँगे, तो आने वाला कल हमारे युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अंततः, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य और हर बच्चे की समग्र विकास यात्रा का मार्गदर्शक होना चाहिए। समय की मांग है कि हम शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी और प्रभावी बनाएं। यही हमारी जिम्मेदारी और देश की प्रगति की कुंजी है।

DMK के किले में सेंध लगाने उतरे विजय
'थलापति' बनाम स्टालिन

तमिलनाडु में सी. विजय जोसेफ़ की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम ने चुनाव में नई चुनौती पेश की है। चेन्नई में DMK के गढ़ को निशाना बनाकर विजय ने खुद को एम.के. स्टालिन के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाई है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जहां अभिनेता से नेता बने सी. विजय जोसेफ़ की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। राज्य की पारंपरिक दिग्गज पार्टियां—द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK)—अब एक नए और उभरते प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही हैं।विजय की रणनीति का केंद्र बना है चेन्नई, जिसे लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का अभेद्य किला माना जाता रहा है। उन्होंने सीधे DMK के इस मजबूत गढ़ को चुनौती देने का फैसला किया है। विजय ने एक ओर तिरुचिरापल्ली (पूर्व) से नामांकन दाखिल कर अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट चुनी है, वहीं दूसरी ओर पेरम्बूर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पेरम्बूर की सीमा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र कोलाथुर से लगती है, जिससे यह मुकाबला और भी प्रतीकात्मक बन गया है। विजय का दो सीटों से चुनाव लड़ना एक सुनियोजित रणनीति है। तिरुचिरापल्ली उन्हें सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है, जबकि पेरम्बूर से उनकी उम्मीदवारी उन्हें सीधे तौर पर स्टालिन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करती है। यह कदम TVK को राज्य की राजनीति में एक गंभीर दावेदार के रूप में पेश करता है।चेन्नई जिला वर्षों से DMK का मजबूत गढ़ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनावों में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यहां सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले भी एम. जी. रामचंद्रन (MGR) और जे. जयललिता जैसे दिग्गज नेता भी इस क्षेत्र में DMK के प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए थे। ऐसे में विजय का चेन्नई में आक्रामक दांव DMK के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।चुनावी समीकरणों की बात करें तो DMK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जबकि AIADMK ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ हाथ मिलाया है। इस बीच TVK खुद को एक तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिससे इस बार चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता दिखाई दे रहा है।TVK ने चेन्नई की कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी के महासचिव एन. आनंद (बुस्सी आनंद) टी नगर से, रणनीतिकार आधारव अर्जुना विल्लिवक्कम से, उप-महासचिव के. राजामोहन एग्मोर से, और पूर्व AIADMK विधायक वी.एस. बाबू कोलाथुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री स्टालिन से होगा।विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता, खासकर युवाओं के बीच, चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। चेन्नई जैसे विविध सामाजिक संरचना वाले क्षेत्र में यदि TVK को सफलता मिलती है, तो वह खुद को एक सर्वस्वीकार्य पार्टी के रूप में स्थापित कर सकती है।कुल मिलाकर, 1967 के बाद से DMK और AIADMK के वर्चस्व वाली तमिलनाडु की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। विजय की एंट्री ने न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को तेज कर दिया है, बल्कि राज्य में एक नए शक्ति संतुलन की संभावना भी पैदा कर दी है।

AAP में आंतरिक फेरबदल, राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी (AAP) में इन दिनों आंतरिक हलचल के बीच एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन सामने आया है। राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर (उप-नेता) के पद से हटा दिया गया है। इस फैसले ने न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे समीकरणों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। AAP ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर इस बदलाव की जानकारी दी। पार्टी के अनुसार, अब राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है। पार्टी के बयान में कहा गया कि आगामी संसदीय सत्रों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है, जिससे उच्च सदन में पार्टी की रणनीति को और मजबूत किया जा सके।इस निर्णय के बाद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को एक भावुक और तीखा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "मुझे खामोश तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता।" उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और व्यक्तिगत असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम AAP के आंतरिक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत हो सकता है। राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी के एक युवा और प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं। उन्होंने संसद में कई मुद्दों को जोर-शोर से उठाया, जिनमें 'पैटर्निटी लीव' को कानूनी अधिकार बनाने की उनकी मांग विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने तर्क दिया था कि बच्चों की परवरिश केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता-पिता दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन भी मिला था। हाल के समय में चड्ढा अपनी संसदीय गतिविधियों के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ उनके वैवाहिक जीवन और हाल ही में उनके पहले बच्चे के जन्म की खबरें भी सुर्खियों में रही हैं, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत जरूर दिया है कि आम आदमी पार्टी में आने वाले समय में और भी संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी इस आंतरिक स्थिति को कैसे संभालती है और इसका असर आगामी संसदीय सत्रों में उसके प्रदर्शन पर क्या पड़ता है।

संसद से पास हुआ जन विश्वास विधेयक
व्यापार को मिलेगी राहत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। बुधवार को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि यह कानून 'विश्वास आधारित शासन' को मजबूत करने और नागरिकों तथा व्यवसायों पर अनुपालन के बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सुधार व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां एक ओर ईमानदार नागरिकों और कारोबारियों को राहत मिलेगी, वहीं जानबूझकर कानून तोड़ने वालों में भय भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से एक संतुलित तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है, जिसमें सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई और उचित दंड का प्रावधान शामिल है। मंत्री ने जानकारी दी कि इससे पहले लाए गए जन विश्वास विधेयक में 183 धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था, जिसे व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसी अनुभव के आधार पर इस बार और अधिक व्यापक सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संशोधन में 1000 से अधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया।विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों द्वारा संचालित 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, जबकि 67 प्रावधानों में जीवन को सुगम बनाने के लिए बदलाव किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक दंड से हटाकर नागरिक और प्रशासनिक तंत्र के तहत लाना है। इस कानून में कारावास जैसे कठोर दंडों की जगह आर्थिक जुर्माने या चेतावनी जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, एक श्रेणीबद्ध प्रवर्तन प्रणाली लागू करने का प्रावधान है, जिसमें पहली बार गलती करने पर चेतावनी दी जाएगी और बार-बार उल्लंघन करने पर ही कड़े दंड लगाए जाएंगे। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि 12 राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसी तरह के सुधार लागू कर चुकी हैं। उन्होंने अन्य राज्यों से भी अपील की कि वे छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार करें, ताकि व्यवसाय और

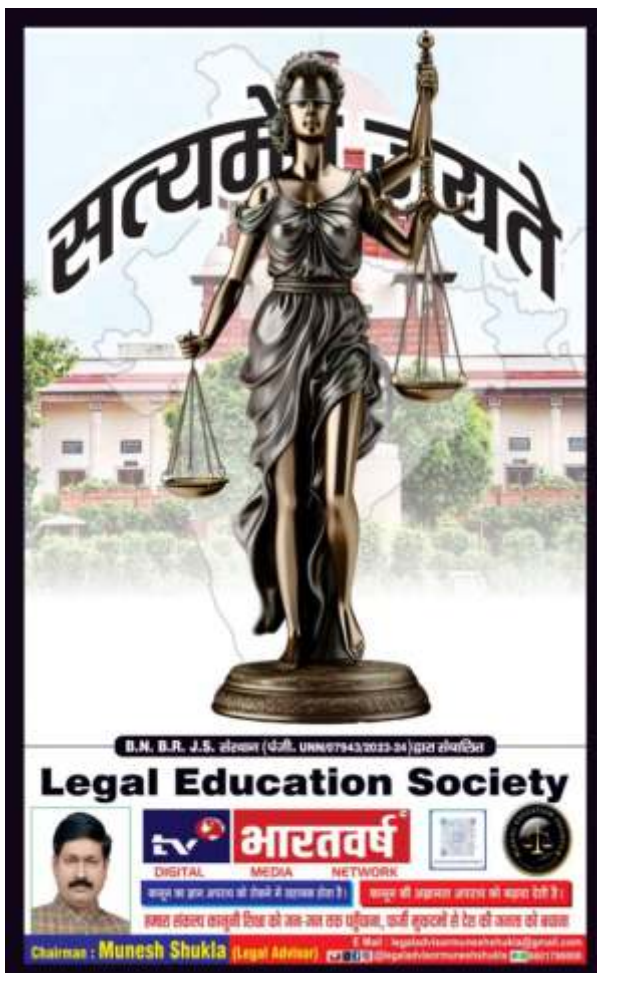

भारतीय बैंकिंग में ऐतिहासिक बदलाव

आरबीएल बैंक में विदेशी निवेश का नया अध्याय

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दुबई स्थित संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दूसरे सबसे बड़े बैंक, एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) को निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक (RBL Bank) में 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद RBL बैंक को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 'विदेशी बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। R B L बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की हिस्सेदारी पर यह मंजूरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और इसे एक वर्ष की वैधता के लिए दी गई है। यह सौदा अक्टूबर 2025 में पेश किया गया था, जब ईएनबीडी ने आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव लगभग 26,853 करोड़ रुपये में रखा था। RBI ने यह स्पष्ट किया कि निवेशक को आरबीएल बैंक की चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना होगा। इसके बाद बैंक को सब्सिडी मॉडल के तहत विदेशी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।RBI के अनुसार, ऐसे बैंक पर पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी मॉडल के तहत नियत प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, निदेशक मंडल बैठकों में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने की शर्त इस पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा बैंक को अपने 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में आवश्यक संशोधन करने और RBI से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मंजूरी भारत सरकार से 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश की स्वीकृति, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999, सेबी नियमों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन होगी। आरबीएल बैंक के मतदान अधिकारों में ईएनबीडी का योगदान 26 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। साथ ही, ईएनबीडी को 'सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस' की शर्त से अस्थायी छूट दी गई है, जब तक कि भारत में उसकी शाखाओं का आरबीएल बैंक के साथ विलय नहीं हो जाता या अधिकतम एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती। यह प्रावधान भारतीय बैंकिंग में विदेशी निवेश की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आरबीआई की मंजूरी के पहले, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ईएनबीडी को आरबीएल बैंक का प्रवर्तक वर्गीकृत करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। साथ ही, जनवरी 2026 में प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भी एमिरेट्स एनबीडी के आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी।इस सौदे के पूरा होने के बाद आरबीएल बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विदेशी बैंक की श्रेणी में आएगा, जिससे उसकी वैश्विक पहचान बढ़ेगी। एमिरेट्स एनबीडी के अनुभव और वित्तीय संसाधन आरबीएल बैंक को स्थिरता, नवाचार और वैश्विक विस्तार में मदद करेंगे। यह विलय न केवल आरबीएल बैंक के लिए बल्कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कदम भारतीय बैंकिंग में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और नए तकनीकी और प्रबंधन मॉडल अपनाने की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। RBL बैंक और एमिरेट्स एनबीडी के बीच यह विलय भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। विदेशी निवेश के माध्यम से बैंक का पूंजीगत ढांचा मजबूत होगा और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आधुनिक प्रबंधन, नियामक सुधार और निवेशकों के विश्वास को और मजबूती मिलेगी। यह सौदा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक और स्थानीय सहभागिता का एक नया अध्याय खोल रहा है, जो आने वाले वर्षों में वित्तीय नवाचार और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए अहम साबित होगा।

डेल स्टेन से प्रेरित होकर तेज गेंदबाज बने औकिब नबी

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने खुलासा किया है कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन से प्रेरित होकर उन्होंने तेज गेंदबाजी की राह चुनी। इस सीजन रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर को पहली बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले औकिब नबी अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं और उन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में मौका मिल सकता है। औकिब नबी ने बताया कि बचपन में वह डेल स्टेन की गेंदबाजी को ध्यान से देखते थे। उनकी तेज गति और स्विंग ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन वह भारत के लिए खेलें। हालांकि, क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को परिवार से शुरू में समर्थन नहीं मिला। उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बनें, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। औकिब नबी की सफलता में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का भी अहम योगदान रहा है। इरफान पठान जब जम्मू-कश्मीर टीम के मेंटोर थे, तब उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सीनियर टीम में मौका दिलाया। औकिब नबी ने बताया कि पठान ने उन्हें गेंदबाजी की बारीकियां सिखाईं और लगातार मार्गदर्शन किया। इरफान पठान ने भी औकिब नबी की तारीफ करते हुए कहा कि वह लंबे स्पैल डालने और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी खासियत यह है कि वह सीम पोजिशन के साथ गेंद को देर से स्विंग करा सकते हैं, जो उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाता है।पठान के अनुसार, औकिब नबी भले ही 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी न करते हों, लेकिन उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी पकड़ती है और बल्लेबाजों को परेशान करती है।

IPL 2027 में होगा बड़ा बदलाव?

मैच बढ़ाने की तैयारी, द्विपक्षीय सीरीज पर संकट

संजू सैमसन CSK के लिए गेम चेंजर, मनोज तिवारी ने किया समर्थन

आईपीएल 2026 में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल रहे हैं। संजू न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं और आवश्यकता पड़ने पर कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। इससे पहले संजू राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रह चुके हैं। आईपीएल 2026 के पहले लीग मैच में उनका बल्ला जमकर नहीं चला, लेकिन पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने साफ कर दिया कि संजू की टीम के लिए अहमियत किसी भी प्रदर्शन से कम नहीं है।क्रिकबज से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि हर खिलाड़ी के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उसके पक्ष में होता है और संजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर का मैच हुआ था, जिसमें संजू टीम की बातचीत में शामिल नहीं थे। इस वजह से अंदाजा लगाया गया था कि कुछ गड़बड़ है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि संजू सैमसन की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भूमिका किसी भी किताब में दर्ज होनी चाहिए।उन्होंने बताया कि संजू के साथ शुरुआत में ज्यादती हुई थी और उन्हें ओपनिंग में खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें मध्यक्रम में मौका मिला और बाद में ओपनिंग का अवसर मिला, तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनका आत्मविश्वास और खेल का दृष्टिकोण टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि संजू सैमसन का आगमन CSK के लिए एमएस धोनी के जैसा क्रेज बनाए रखेगा। उनके आने से टीम में नेतृत्व और अनुभव का सही संतुलन बना है। तिवारी ने यह भी कहा कि संजू अब धोनी के ब्रांड को भी आगे बढ़ाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, और उनकी उपलब्धियों ने टीम और फैंस दोनों के लिए उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।संजू सैमसन की यह यात्रा दर्शाती है कि सही मौके और सही मानसिकता के साथ कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम और देश के लिए यादगार मुकाम हासिल कर सकता है।

कराची किंग्स में सब ठीक! वॉर्नर ने अफवाहों पर लगाया विराम

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का यह सीजन शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रहा है। मैदान पर बॉल टैंपरिंग, होटल में सुरक्षा को लेकर गड़बड़ी और अन्य घटनाओं के बीच अब इस सीजन का नया विवाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली से जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने फैंस और क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। इस वीडियो में डेविड वॉर्नर और मोइन अली का व्यवहार कुछ संदिग्ध नजर आया, जिसके चलते सवाल उठने लगे कि क्या टीम में कोई अंदरूनी परेशानी है। हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई खुद डेविड वॉर्नर ने सामने रखी। वॉर्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि, "मैंने हैदर अजहर से कहा कि पहले जाओ और हाथ मिलाओ। यह सब एक मजाक था, किसी तरह की समस्या नहीं थी।"कराची किंग्स के स्ट्रेटेजी हेड और टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि टीम में कोई असहमति नहीं है और यह सब खिलाड़ियों का हल्का-फुल्का मजाक था। PSL के अधिकारियों और टीम प्रबंधन ने साफ किया है कि टीम में कोई भी विवाद नहीं है और खिलाड़ी पूरी तरह से मैच पर फोकस कर रहे हैं। इस सीजन में टीमों और खिलाड़ियों को खेल के अलावा सोशल मीडिया पर होने वाले विवादों से भी निपटना पड़ रहा है, लेकिन कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने साफ किया कि टीम में सबकुछ सामान्य और सकारात्मक है।

11 साल की बोधना शिवानंदन बनी इंग्लैंड की टॉप महिला शतरंज खिलाड़ी

शतरंज की दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों का बोल बाला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 11 साल की भारतवंशी बच्ची बोधना शिवानंदन ने इतिहास रच दिया है। बोधना ने अपने पिता के पुराने शतरंज बोर्ड से खेल की शुरुआत की और यूट्यूब के माध्यम से शतरंज की बारीकियां सीखीं। आज, 2366 की बेहतरीन रेटिंग के साथ वह इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। बोधना ने कम उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उनका जुनून, परिवार का समर्थन और आत्मविश्वास उन्हें शिखर तक ले गया। बोधना का परिवार मूल रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले का रहने वाला है। उनके पिता शिवानंदन वेलायुथम 2007 में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे। बोधना का जन्म 7 मार्च 2015 को लंदन में हुआ।अब बोधना इंग्लिश फेडरेशन की टॉप महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी रेटिंग ब्रिटेन की बाकी सभी शीर्ष महिला खिलाड़ियों से भी बेहतर है। इसके अलावा, वह पहली बार दुनिया की टॉप 100 महिला खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हुई, जहां वह 72वें स्थान पर हैं।बोधना ने अपनी उपलब्धियों का सिलसिला बहुत कम उम्र में शुरू किया। उन्होंने यूरोपीय स्कूल चैम्पियनशिप में अपने सभी 24 मुकाबले जीतकर तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 2024 में, चेस ओलंपियाड के लिए चुने जाने पर वह किसी भी खेल में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं। 2025 में उन्होंने ब्रिटिश शतरंज चैम्पियनशिप में 60 साल के ग्रैंडमास्टर को हराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बोधना ने पिछले साल यूरोपीयन क्लब कप में यूक्रेन की पूर्व महिला विश्व चैम्पियन ग्रैंडमास्टर मारिया मुजिचुक को हराकर सबको चौंका दिया था। उनकी इस उपलब्धि को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी सराहा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ 11 साल की उम्र में इंग्लैंड की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनने पर बोधना शिवानंदन को बधाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद भी बोधना के साथ डाउनिंग स्ट्रीट के बगीचे में खेला था और उनकी सफलता उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करती। बोधना शिवानंदन की कहानी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी मेहनत, लगन और परिवार का सहयोग यह संदेश देता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

ईरान गए इंडियन ने बताई कहानी

पुलवामा के बाइकर की जांबाजी

कश्मीर से बाइक पर निकले एक भारतीय बाइकर की कहानी इन दिनों चर्चा में है. ईरान, इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों में उन्हें ऐसी मेहमाननवाजी मिली.आखिर कौन हैं ये बाइकर और क्या है उनकी पूरी कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में...

प्रणय उपाध्याय, आजतक

उमर इकबाल ने अपने अनुभवों से लोगों को चौंका दिया.

कश्मीर से निकले एक भारतीय बाइकर ने अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान इराक, ईरान और अफगानिस्तान में मिली अनोखी मेहमाननवाजी की कहानी शेयर की है. आजतक के संवाददाता प्रणय उपाध्याय के साथ बातचीत में बाइकर ने बताया कि कई जगहों पर बॉर्डर चेकिंग तक नहीं हुई और लोग खुद आगे बढ़कर उन्हें खाना और ठहरने की जगह देते रहे. इस बाइकर, उमर इकबाल, ने अपने अनुभवों से लोगों को चौंका दिया. उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई बार उन्हें सामान्य चेकिंग से भी नहीं गुजरना पड़ा. उनके मुताबिक, जैसे ही लोगों को पता चलता था कि वह भारत से हैं, उनका व्यवहार और भी ज्यादा अपनापन भरा हो जाता था. उमर ने कहा कि जब लोगों ने सुना कि मैं इंडिया से हूं, तो मेरी बाइक को टच तक नहीं किया. कोई चेकिंग नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि कई जगहों पर लोग खुद आगे आकर उन्हें खाना ऑफर करते थे और रुकने के लिए जगह देते थे. हर जगह उन्हें एक मेहमान की तरह सम्मान मिला. हालांकि, उनकी यात्रा का एक डरावना पहलू भी सामने आया. पुलवामा, कश्मीर के 27 वर्षीय उमर इकबाल ने ईरान में अमेरिका-ईरान तनाव के दौरान अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि एक समय वह खाली हाईवे पर बाइक चला रहे थे, तभी उनके ऊपर से बार-बार मिसाइलें गुजर रही थीं. ⊙

तेल अवीव के आसमान में कौओं का झुंड?

जब भी जंग का माहौल बनता है, उसके साथ प्रोपेगेंडा भी तेजी से फैलने लगता है. ऐसी कई खबरें सामने आती हैं, जिनमें सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है. पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसे तेल अवीव का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि शहर के आसमान में हजारों कौए मंडरा रहे हैं. वीडियो में आसमान काले झुंड जैसा नजर आता है. ⊙

'कृष का गाना सुनेगा' वाले की किस्मत पलटी

सोशल मीडिया के दौर में कब किसकी किस्मत पलट जाए, यह कहना मुश्किल है. एक वायरल रील किसी को रातों-रात स्टार बना देती है.

कुछ ऐसा ही हुआ 'धूम' यानी पिंटू प्रसाद के साथ. धूम, जिनका असली नाम पिंटू प्रसाद बताया जा रहा है, बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं. साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले पिंटू अचानक तब सुर्खियों में आए, जब उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. दरअसल, 'क्रिस का गाना' वाले ट्रेंड में उनकी एक क्लिप तेजी से शेयर होने लगी.

इस वीडियो में उनके एक्सप्रेशन और अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया. देखते ही देखते यह क्लिप इतनी वायरल हुई कि हर तीसरी-चौथी रील में वही नजर आने लगे. यहीं से उन्हें 'धूम' नाम मिला और वह इंटरनेट सेंसेशन बन गए. अब एक बार फिर धूम चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है. ⊙

1.6 लाख फीस है 'टाओटाओ' के किंडरगार्टन की

इंसानों से भी लग्जरी है डॉगी की लाइफ

चीन से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. टाओटाओ नाम की युवती अपने 6 महीने के सैमोयड कुत्ते को लेकर चर्चा में हैं.

शंघाई में रहने वाली यह युवती अपने पालतू को एक लग्जरी डॉग किंडरगार्टन भेज रही हैं और इसके लिए हर महीने करीब 12 हजार युआन, यानी लगभग 1.6 लाख रुपये खर्च कर रही हैं. टाओटाओ का कहना है कि वह नौकरी में काफी व्यस्त रहती हैं और अपने डॉगी को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं. इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया, ताकि उनके पालतू की देखभाल सही तरीके से हो सके. उनके मुताबिक, यह सिर्फ खर्च नहीं बल्कि अपने पालतू की भलाई के

लिए लिया गया एक जरूरी कदम है.साउथ मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,यह डॉग किंडरगार्टन कोई सामान्य डे-केयर सेंटर नहीं है, बल्कि एक प्रीमियम सुविधा है. यहां कुत्तों का पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट टेस्ट किया जाता है, ताकि उनके स्वभाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके. इसके साथ ही बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे भौंकने या आक्रामकता जैसी आदतों को कंट्रोल किया जा सके.इतना ही नहीं, यहां कुत्तों को दूसरे कुत्तों के साथ खेलने और घुलने-मिलने का मौका भी मिलता है, जिससे उनका सामाजिक व्यवहार बेहतर होता है. डेली बोर्डिंग के साथ पिकअप और छोड़ने की सुविधा भी दी जाती है.

इसके अलावा, मालिक और पालतू के बीच संबंध मजबूत करने के लिए खास इंटरैक्शन क्लास भी होती हैं. ⊙

'रामायण' का टीज़र रिलीज़ होते ही मचा धमाल

सोशल मीडिया पर छाए रणबीर कपूर

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जारी किए गए 'रामायण' के टीज़र ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आ रहे हैं। उनका शांत, गंभीर और दिव्य व्यक्तित्व दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। टीज़र में उनकी झलक ने ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में दर्शकों ने उनके लुक और अभिनय की सराहना करते हुए इसे अब तक का सबसे प्रभावशाली राम अवतार बताया है।हालांकि, जहां एक ओर टीज़र को खूब सराहना मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म का प्रस्तुतीकरण बेहतर है और यह 'आदिपुरुष' से काफी आगे नजर आता है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। इस बीच, दिवंगत अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टीज़र की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म का विजुअल और प्रस्तुति प्रभावशाली है, लेकिन निर्माताओं को रामायण की मूल भावना और धार्मिक संवेदनाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विंदू दारा सिंह ने यह भी कहा कि दर्शकों की आस्था इस विषय से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की रचनात्मक छूट लेते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मूल कथा से छेड़छाड़ की गई, तो दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिल्म के बजट को लेकर भी चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि 'रामायण' का बजट लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर के बीच है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल करता है। इतने बड़े बजट के साथ यह फिल्म तकनीकी रूप से भी बेहद भव्य और उच्च स्तर की होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्माताओं ने फिल्म को दो भागों में रिलीज़ करने की योजना बनाई है, जिसमें पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगा। इस बड़े प्रोजेक्ट से बॉलीवुड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर, 'रामायण' का टीज़र दर्शकों के बीच उत्साह और बहस दोनों का कारण बना हुआ है। अब सभी की नजरें फिल्म की रिलीज़ पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि यह फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।

2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का अखिलेश यादव ने किया संकल्प

जनता से अपील: सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं

अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को लखनऊ में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने विपक्षी आवाजें दबाने, शिक्षा, रोजगार और महिला कल्याण की उपेक्षा का आरोप लगाया। यादव ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया और जनता से सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 अप्रैल को भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे विपक्षी आवाजों को दबाने और शिक्षा, रोजगार तथा महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करने का दोषी ठहराया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, "यह सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं कर रही। जनता को चाहिए कि वे सरकार के खिलाफ एकजुट हों। "अखिलेश यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि संतों का अपमान किया जा रहा है और प्रशासन का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ने का कारण भी यही बताया। संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनमानी के अनुसार कार्य कर रही है और यह संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 2027 में सरकार बनाने के लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर शोषित और पीड़ित लोगों को एकजुट करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, "हमें 2027 में समाजवादी सरकार बनानी ही होगी ताकि प्रदेश में जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके।" शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भाजपा सरकार की विफलताओं का भी उल्लेख किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों की हालत बिगाड़ दी है और कई शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्थापित किए गए 'अभिनव विद्यालय' और 'संस्कृति विद्यालय' का हवाला देते हुए बताया कि छात्रों की मदद के लिए लैपटॉप भी वितरित किए गए थे। लेकिन अब सरकारी विद्यालयों की स्थिति और भी खराब हो गई है। सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं की आलोचना करते हुए यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का 'ग्रीन कॉरिडोर' वास्तव में 'बर्बादी का कॉरिडोर' बन गया है। उन्होंने चौराहों पर बैरिकेडिंग और जनता को हो रही असुविधा का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर यह स्थिति बनाई है। शहरी विकास और सौंदर्यीकरण के प्रयासों पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिवरफ्रंट परियोजना का उद्देश्य गोमती नदी को साफ करना था, लेकिन इसके बजाय केवल बदबू फैल रही है। उन्होंने पूछा कि यहां किस तरह की क्रूज सेवा चलाने की योजना बनाई जा रही है और जनता को इसका लाभ कैसे मिलेगा।अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जनता से एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की और कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी।

वसूली के आरोप ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता, जांच के दायरे में कई अधिकारी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में एक थानेदार पर ढाई लाख रुपये वसूली के आरोप ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की जांच के बाद आरोपित अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना तब सामने आई जब एक युवक ने शिकायत की कि थानेदार ने उसे थाने में बुलाकर बिना किसी कानूनी कारण के ढाई लाख रुपये की मांग की और उसे धमकाया। सूत्रों के अनुसार, युवक ने बताया कि थानेदार ने पैसे न देने पर परेशान करने की धमकी दी। बाद में युवक को थाने से छोड़ दिया गया। हालांकि, युवक ने यह घटना नजरअंदाज नहीं की और सीधे पुलिस कमिश्नर कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की। प्रारंभिक जांच में कुछ गवाह और साक्ष्य भी सामने आए हैं, जिनसे आरोपों की पुष्टि हो रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विभागीय नियमों के अनुसार आरोपी थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। इसका मतलब है कि थानेदार फिलहाल अपने पद का कार्य नहीं करेगा और जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर थानेदार के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जनता से भी अपील की गई कि यदि किसी अधिकारी द्वारा अवैध वसूली या अन्य अनुचित व्यवहार किया जाए तो तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दें।

लखनऊ के सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग अब सिर्फ एक क्लिक दूर!

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

अब लखनऊ के नागरिक नगर निगम द्वारा संचालित कल्याण मंडपों और सामुदायिक केंद्रों (कम्युनिटी हॉल) की बुकिंग घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इस नई सुविधा के साथ ही गुरुवार को नगर निगम ने 456 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, जो शहर की बुनियादी संरचना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर झंडी वाला पार्क (जोन-1) में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे पहले नागरिकों को मंडप या सामुदायिक केंद्र बुक कराने के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब वे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्धता देख सकेंगे, शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और बुकिंग पक्का कर सकेंगे। इसकी योजना से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और आम नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी। नगर निगम ने कल्याण मंडपों और सामुदायिक केंद्रों के लिए शुल्क भी निर्धारित किए हैं, जो स्थान के आकार और श्रेणी के आधार पर भिन्न हैं। प्रमुख केंद्रों में महानगर कल्याण मंडप, जियामऊ कल्याण मंडप, विकास नगर मंडप, मानसरोवर मंडप आदि शामिल हैं, जिनके किराए लाखों रुपये तक हैं। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इन केंद्रों की बुकिंग अब तेज़ और सुविधाजनक होगी। महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि नगर निगम की यह पहल लखनऊ को एक आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ₹29.62 करोड़ की लागत से तैयार की गई 456

परियोजनाएं केवल विकास कार्य नहीं हैं, बल्कि लखनऊ के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव हैं।इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, नालियों की सुदृढ़ीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार तथा अन्य शहरी विकास कार्य शामिल हैं। महापौर ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिनकी मेहनत से यह काम संभव हुआ है। उन्होंने नागरिकों से भी इस डिजिटल पहल का लाभ लेने तथा शहर के विकास में सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर नगर निगम के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरनजीत गांधी, पार्षद सुशील तिवारी 'पम्मी', नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी

1076 कर्मचारियों ने वेतन मुद्दे पर किया प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से जुड़े लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों ने अपने वेतन व कार्य स्थितियों को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ कम वेतन और बार-बार वेतन भुगतान में देरी जैसे अन्याय हो रहा है। प्रदर्शन का क्रम गोमतीनगर स्थित साइबर टावर से शुरू होकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारियों को जबरन बसों में बैठा दिया गया, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप है कि उन्हें शुरुआत में ₹15,000 के वेतन का वादा किया गया था, लेकिन असल में उन्हें केवल ₹7,000-₹8,000 ही वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा, कई कर्मचारियों के दो महीने से वेतनराशि भी लंबित है, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि काम के दौरान मोबाइल फोन जमा करवा लिए जाते हैं, और कार्यालय में लंबी ड्यूटी के बावजूद उचित सुविधाएँ नहीं मिलतीं। साइबर टावर से निकलकर जब कर्मचारी लोहिया पथ की ओर मार्च कर रहे थे, तो पुलिस ने पहले उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। बाद में संगीत नाटक अकादमी के पास बैरिकेडिग कर प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारी आगे बढ़ते रहे। इस बीच पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़क किनारे हटाया और जबरदस्ती बसों में बैठाया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और अफरातफरी का माहौल बन गया।प्रदर्शन के कारण लोहिया पथ तथा आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई, जिससे आम आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बदसलूकी करने और उनके संवैधानिक अधिकारों को रोकने का आरोप लगाया है। वे मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी समस्याओं को सीधे रखने की इच्छा जताते रहे।

लखनऊ में बेटी होने पर महिला पर ससुराल वालों ने किया हमला

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी लखनऊ में एक जोरदार घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि बेटी को जन्म देने के कारण ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा और बाद में घर से निकाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पति समेत चार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह घटना शहर के एक निवासी मोहल्ले में हुई, जब महिला हाल ही में एक स्वस्थ बेटी को जन्म देने के बाद घर लौट रही थी। महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष को लड़का चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद से ही उसके पति तथा अन्य रिश्तेदारों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। आरोप है कि घर में रहते समय उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित, गाली-गलौज और मानसिक आरोपों का सामना करना पड़ा, और बेटी को जन्म देने के बाद ही ससुराल वालों ने गंभीर रूप से मारपीट की। महिला ने बताया कि उसके साथ बिना किसी वास्तविक कारण के मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया।गंभीर बात यह है कि महिला ने आरोप में ये भी कहा कि उसे बार-बार कहा गया कि "बेटी होने के कारण रिश्ता पूरा नहीं हुआ" और इसीलिए उसे अपमानित किया गया। परिवार में तनाव हर रोज बढ़ता गया और व्यवहार कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद पीड़िता ने पड़ोसियों से मदद मांगी और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।

लखनऊ में 16 घंटे के लिए बंद रहेंगी UPPCL की ऑनलाइन सेवाएं

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सूचना जारी की है कि राज्यभर में अपनी ऑनलाइन सेवाएँ 16 घंटे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। यह बंदी 3 अप्रैल 2026 की रात 10 बजे से 4 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे तक लागू होगी, जिसमें लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इसके चलते उपभोक्ता इस दौरान बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज और अन्य सेवा काम नहीं कर पाएंगे। UPPCL ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उसकी आरएमएस बिलिंग प्रणाली में मैंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन कार्य के लिए लिया गया है। इस सिस्टम अपग्रेड का उद्देश्य सेवाओं को और अधिक सुचारू, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि भविष्य में बिल भुगतान जैसी सुविधाओं में तकनीकी समस्याएँ कम हों और डिजिटल सेवाएँ बेहतर हो सकें।इस दौरान बिजली विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल, मोबाइल ऐप और कंज्यूमर सेवाएँ पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो इस दौरान बिल का भुगतान करना चाहते हैं या स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराना चाहते हैं; वे सुविधाएँ इस 16-घंटे के दौरान उपलब्ध नहीं रहेंगी। UPPCL की अपील है कि उपभोक्ता इस अवधि का ध्यान रखते हुए पहले ही अपने बिजली बिल का भुगतान कर लें और स्मार्ट मीटर बैलेंस रिचार्ज कर लें, ताकि बंदी के दौरान बिजली कटौती या किसी अन्य असुविधा का सामना न करना पड़े। खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है जिनका मीटर बैलेंस कम है या जिनकी आगामी बिल की अंतिम तिथि निकट है। यह शटडाउन केवल बिल भुगतान और रिचार्ज तक ही सीमित नहीं है; इसके चलते बिल जनरेशन, लोड एन्हांसमेंट (भार वृद्धि) के आवेदन, नया कनेक्शन प्राप्त करने के कार्य और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने जैसी सेवाएँ भी प्रभावित रहेंगी। ऐसे में जो उपभोक्ता इन दिनों में कोई नया अनुरोध दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें भी पहले ही आवश्यक कदम उठाना होगा। UPPCL का कहना है कि यह व्यवधान राज्यभर के सभी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को) के सिस्टम पर लागू होगा, यानी लखनऊ के अलावा बड़े शहरों तथा ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएँ बंद रहेंगी। भले ही यह अस्थायी बंदी उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक साबित हो सकती है, लेकिन विभाग

का कहना है कि यह एक जरूरी तकनीकी कदम है जिससे भविष्य में उपभोक्ता अनुभव बेहतर होगा और डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। विभाग ने भरोसा जताया है कि निर्धारित समय पर सभी सेवाएँ फिर से बहाल कर दी जाएंगी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे UPPCL की वेबसाइट या कस्टमर हेल्पलाइन 1912 से किसी भी सहायता या जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं

उन्नाव तैयार: 2027 की जनगणना होगी पहली बार पूरी तरह डिजिटल!

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में जनगणना-2027 की तैयारियाँ पूरी गति से चल रही हैं और प्रशासन ने इसे आगामी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के रूप में लिया है। इस बार होने वाली जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण दोनों की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज होगी। जनगणना 2027 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला चरण मकानों की सूची और आवास गणना पर केंद्रित रहेगा और दूसरा चरण सीधे जनसंख्या की गणना करेगा। यह जानकारी कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अधिकारियों को दी। प्रथम चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें मकानों और घरों का विस्तृत सूचीकरण और उनके विवरण दर्ज किए जाएंगे। इसके पूर्व 07 मई से 21 मई 2026 तक जनगणना का स्व-गणना विकल्प जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें नागरिक अपनी जानकारी स्वयं डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसे पूरा करने पर उन्हें एक SE ID मिलेगा, जिसे बाद में फील्ड प्रगणक के सत्यापन के लिए दिखाना होगा।दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच पूरी जनसंख्या की गणना करेगा, जिसमें देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक और डेमोग्राफिक जानकारी संग्रहीत होगी। इस तरह की प्रक्रिया अब तक भारत की जनगणना में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल रूप में हो रही है। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रगणक और सुपरवाइजरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए और सटीक डेटा दर्ज करने के लिए उन्हें डिजिटल उपकरणों–मोबाइल ऐप और पोर्टल के उपयोग–का अभ्यास कराया जाए। उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, इसलिए तैयारी पहले से सुनिश्चित कर ली गई है। कोई भी कर्मचारी, जो गंभीर बीमारी, असमर्थता या दिव्यांगता का सामना कर रहा है, उसे फील्ड ड्यूटी पर न लगाया जाए। उन्नाव प्रशासन ने जनगणना को क्षेत्र में त्रुटिरहित और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए ID जनरेशन और लॉगिन प्रक्रियाएं पहले से ही नियंत्रित की जा रही हैं। प्रजेंटेशन के माध्यम से यह भी बताया गया कि नागरिक अपने घरों से ही अपने डेटा को संबद्ध पोर्टल पर भर सकते हैं, जिससे गणना प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और कार्य तेजी से पूरा होगा। राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश में यह जनगणना भी दो चरणों में आयोजित होगी – पहले मकानों व सूचीकरण का कार्य और बाद में जनसंख्या गणना। इसका उद्देश्य देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास को डिजिटल रूप से संपन्न कराना है, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं, संसाधन आवंटन, नीति और प्रशासनिक निर्णयों में सटीक डेटा उपलब्ध हो सके। इस तरह की डिजिटल पहल से उन्नाव समेत पूरे प्रदेश में जनगणना 2027 को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है, जिससे डेटा की गुणवत्ता में सुधार और सरकार की योजनाओं को वास्तविक समय में आधार प्रदान करने में मदद मिलेगी।

उन्नाव में मिड-डे-मील विवाद: शिक्षक ने छात्र को पीटा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हीरा मनपुरवा प्राथमिक विद्यालय में एक नए प्रकार का दुखद मामला सामने आया है, जिसमें मिड-डे-मील के लिए लकड़ी लाने से मना करने पर प्रधान अध्यापक द्वारा एक छात्र को पीटने का आरोप दर्ज हुआ है। यह घटना शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में चिंता का विषय बन गई है, और स्थानीय पुलिस तथा शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। यह मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रबड़ी गांव का है, जहाँ के एक अभिभावक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र को प्रधान अध्यापक शिशिर यादव ने मिड-डे-मील के लिए लकड़ी लाने से इनकार करने पर पीटा। पीड़ित छात्र का कहना था कि वह पढ़ाई पूरी कर टीसी तथा मार्कशीट लेने स्कूल गया था, लेकिन प्रधान अध्यापक ने उससे लकड़ी बिनवाने को कहा, जो उसके लिए संभव नहीं था। लकड़ी नहीं लाने पर उसी वक़्त उसे डाँट और मारपीट का सामना करना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।घटना को लेकर पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर प्रधान अध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें मारपीट के अलावा छात्र के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार तथा अनुचित आदेश देने जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक (सीओ) मामले की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जल्द करने की बात कही जा रही है।

उन्नाव से साक्षी महाराज का संदेश

भाजपा बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

भाजपा के वरिष्ठ सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में राजनीतिक बदलाव संभव है और इस संदर्भ में उन्होंने अपने साथी भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के कुछ विवादित बयानों का समर्थन भी किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की संभावनाएँ मजबूत हैं और आगामी चुनावों में परिवर्तन की लहर देखी जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और यह बदलाव के संकेत हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर परिणाम का अनुमान नहीं लगाया, लेकिन यह संकेत दिए कि भाजपा बंगाल में वोटरों के बीच बेहतर स्थिति में पहुँच रही है।साक्षी महाराज ने अपने बयान में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के कुछ राजनीतिक विचारों से वह सहमत हैं और उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने पहले भी विभिन्न मौकों पर राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिए हैं, जिन्हें लेकर चर्चा बनी रही है। साक्षी महाराज की इस समर्थन भरी टिप्पणियों ने भाजपा के अंदरूनी एकता और संगठनात्मक रुख पर भी ध्यान खींचा है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियाँ—भाजपा और टीएमसी—अपने-अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करने में जुटी हैं। साक्षी महाराज के बयान और उनके द्वारा बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन भाजपा के भीतर की रणनीतिक सोच और राज्य में पार्टी की चयनित दिशा को भी उजागर करता है। कुल मिलाकर, साक्षी महाराज का बयान भाजपा के चुनावी बयानबाज़ी को और जीवंत बनाता है और बंगाल के आगामी चुनावों में राजनीतिक तीव्रता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। आगामी महीनों में दोनों प्रमुख दलों के रणनीतिक कदम और जनमत का रुझान ध्यान के केंद्र में रहेगा।

उन्नाव के आनंद घाट पर बनारस जैसी भव्य आरती स्थल निर्माण की शुरुआत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले के प्रसिद्ध आनंद घाट पर एक भव्य आरती स्थल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे बनारस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की बड़ी पहल का परिणाम है, जिसका उद्देश्य घाट को न केवल पूजा-अर्चना के लिए सुविधाजनक बनाना है, बल्कि इसे एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरने देना है। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि घाट पर बनने वाला आरती स्थल साढ़े एक करोड़ रुपये (₹1.05 करोड़) की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत घाट पर सीढ़ियों और पक्की संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से पूजन और आरती में भाग ले सकें। घाट के सौंदर्यीकरण के लिए दक्ष तकनीक और निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह स्थल बारहमासा पूजा-अर्चना और आयोजनों के लिए उपयोगी हो सके।स्थानीय नगर पालिका के अधिकारियों और पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण के दौरान कहा कि काम को अगले दो महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में संरचना मजबूत बनाई जा सके और निर्माण कार्य में कोई देरी न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में घाट पर होने वाले धार्मिक आयोजन और सामाजिक कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सकें। आनंद घाट पर आरती स्थल का विकसित होना स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह घाट पहले से ही श्रद्धा और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है और अब इसे बनारस जैसे प्रमुख पवित्र स्थलों की तरह आधुनिक और संरचित रूप देने की दिशा में कदम उठाया गया है। घाट के विकास से न केवल स्थानीय लोगों को पूजा-अर्चना की सुविधा मिलेगी, बल्कि श्रद्धालु और पर्यटक भी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के लिए आकर्षित होंगे।स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के विकास कार्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। घाट के आस-पास सफाई, रोशनी, बैठने की व्यवस्था, पानी की सुविधा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा ताकि श्रद्धालु घाट पर अपने समय का आनंद उठा सकें। इस परियोजना को स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि नदी के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित न हो। आगामी महीनों में पूरा होने के बाद यह आरती स्थल धार्मिक आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद उन्नाव में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह घाट आसपास के जिलों तथा प्रदेश के नागरिकों के लिए भी एक आकर्षक स्थल के रूप में उभर सकता है।

उन्नाव में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटवाए और बुलडोजर चलाकर भूमि को मुक्त कराया। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की गई, जिसमें प्रशासन ने करीब एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली भूमि को कब्जामुक्त कराकर वापस सरकारी नियंत्रण में ले लिया।उन्नाव प्रशासन ने यह कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड और अदालत के आदेश के आधार पर की, क्योंकि भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया जा रहा था और उसके रिकॉर्ड में सरकारी दर्ज भूमि को निजी उपयोग में बदल दिया गया था। अवैध कब्जे से न केवल सरकारी संपत्ति का हनन हो रहा था, बल्कि उससे जिले में नियमों के उल्लंघन का दबाव भी बढ़ रहा था, जिसके चलते उच्च न्यायालय ने प्रशासन को सख्ती से निर्देश दिए। प्रशासन ने चले अभियान में बुलडोजर का उपयोग किया और अतिक्रमणों सहित अवैध ढांचे को ढहा दिया। भूमि मुक्त कराने के बाद उस पर सरकारी बोर्ड लगाया गया और चारों ओर फेंसिंग भी की गई, ताकि भविष्य में किसी द्वारा फिर से कब्जा न किया जा सके। उन्नाव के जिला अधिकारी ने बताया कि यह भूमि अब पूरी तरह से सरकारी उपयोग के लिए सुरक्षित कर दी गई है और आगे इस पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अनुदानित यूरिया का गलत उपयोग रोकने प्रशासन की सख्त कार्रवाई

उन्नाव में अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग की आशंका के बीच प्रशासन ने जांच-पड़ताल तेज कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने शासन के निर्देश पर संयुक्त टीम का गठन किया और जिले की औद्योगिक इकाइयों में छापेमारी कर अनुदानित यूरिया के गलत उपयोग के सबूत तलाशे। जांच के दौरान टीम ने यूरिया के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं ताकि आगे की विधिक कार्रवाई के लिए वैज्ञानिक परीक्षण कराए जा सकें। शासन की ओर से गठित टीम में कृषि विभाग, जिला उद्योग केंद्र और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने जिले की कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इन इकाइयों में उन उत्पादों में यूरिया का अनधिकृत उपयोग होने की आशंका जताई गई थी, जिनमें यूरिया वैध रूप से नहीं उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि प्लाईवुड, पशु आहार, साबुन, अल्कोहल निर्माण या डीजल उत्सर्जन तरल (DEF) जैसे उत्पादों में अनुदानित यूरिया मिलावटी रूप से मिलाया जा रहा हो सकता है। जांच को लेकर यह समझा जा रहा है कि अगर अनुदानित यूरिया का दुरुपयोग होता है, तो इससे सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग और काला कारोबार बढ़ सकता है, जो किसानों के लिए निर्धारित किफायती यूरिया तक उनकी पहुँच को प्रभावित कर सकता है।

आगरा में 20 वर्षों की परंपरा जारी
भव्य श्री हनुमान जन्म महोत्सव की धूम

आगरा में श्री हनुमान जन्म महोत्सव का 20वां वर्ष भव्य रूप से मनाया गया। 31 झांकियों, 7 बैंड और 55 कलाकारों के साथ आठ किलोमीटर लंबी शोभायात्रा निकली। गौ सम्मान अभियान और बच्चों के देवी-देवताओं के रूप ने उत्सव को आकर्षक बनाया।

श्री हनुमान जन्म महोत्सव पिछले 20 वर्षों से लगातार धूमधाम से मनाया जाता रहा है इसी प्रकार आज पुनः 31 झांकी 7 बैंड 55 कलाकार रास्ते मेंश्री हनुमान जन्म महोत्सव पिछले 20 वर्षों से लगातार धूमधाम से मनाया जाता रहा है इसी प्रकार आज पुनः 31 झांकी 7 बैंड 55 कलाकार रास्ते में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा निकली गई यात्रा के दौरान गौ सम्मान आवाहन अभियान की भी एक झांकी साथ में रही झांकियां पर छोटे-छोटे बच्चों को देवी देवताओं के स्वरूप में सजाकर विठाला गया और उनकी प्रतिभाओं को दर्शाया गया जिससे कि सनातन धर्म को संस्कृति को अपनी सभ्यता को और ऊर्जा मिल सके इस प्रकार संपूर्ण आयोजन में क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष बच्चे हजारों की संख्या में यात्रा में शामिल रहे समापन एक विशेष केंद्र अंजनी धाम पर हुआयह यात्रा श्री सीताराम मंदिर से प्रारंभ होकर थाना जगदीशपुर क्षेत्र के बोदला चौराहे से पश्चिम पुरी की ओर रास्ते पर होते हुए आवास विकास के समस्त सेक्टर में भ्रमण करती हुई अंजनी धाम पहुं ची मुख्य अतिथि श्री राजेश जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद ,भागवत आचार्य पूनम किशोरी जी ,और क्षेत्रीय विधायक पार्षद उपस्थित रहे कार्यक्रम संयोजक प्रांत उपाध्यक्ष सुनील पाराशर जी विनोद गर्गाचार्य करण गर्ग प्रदीप शर्मा राजकुमार पथिक पार्षद जितेंद्र पाराशर शिवम दुबे गुंजन पाराशर हरिओम शर्मा सैकड़ो बजरंगी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के साथ सब कुशल यात्रा को संपन्न कराया मंच का संचालन विनोद गर्ग आचार्य राजकुमार पथिक ने किया। अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा निकली गई यात्रा के दौरान गौ सम्मान आवाहन अभियान की भी एक झांकी साथ में रही झांकियां पर छोटे-छोटे बच्चों को देवी देवताओं के स्वरूप में सजाकर विठाला गया और उनकी प्रतिभाओं को दर्शाया गया जिससे कि सनातन धर्म को संस्कृति को अपनी सभ्यता को और ऊर्जा मिल सके इस प्रकार संपूर्ण आयोजन में क्षेत्र के सभी स्त्री पुरुष बच्चे हजारों की संख्या में यात्रा में शामिल रहे समापन एक विशेष केंद्र अंजनी धाम पर हुआयह यात्रा श्री सीताराम मंदिर से प्रारंभ होकर थाना जगदीशपुर क्षेत्र के बोदला चौराहे से पश्चिम पुरी की ओर रास्ते पर होते हुए आवास विकास के समस्त सेक्टर में भ्रमण करती हुई अंजनी धाम पहुं ची मुख्य अतिथि श्री राजेश जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद ,भागवत आचार्य पूनम किशोरी जी ,और क्षेत्रीय विधायक पार्षद उपस्थित रहे कार्यक्रम संयोजक प्रांत उपाध्यक्ष सुनील पाराशर जी विनोद गर्गाचार्य करण गर्ग प्रदीप शर्मा राजकुमार पथिक पार्षद जितेंद्र पाराशर शिवम दुबे गुंजन पाराशर हरिओम शर्मा सैकड़ो बजरंगी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन के साथ सब कुशल यात्रा को संपन्न कराया मंच का संचालन विनोद गर्ग आचार्य राजकुमार पथिक ने किया।

खिलौना पिस्टल दिखाकर दुकान में घुसा अपराधी जोड़ा

अयोध्या में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुर्का पहनकर लूटपाट करने वाली महिला की पहचान हिंदू के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि 4 महीने की गर्भवती महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक दुकान से ज्वेलरी लूट की। इस दौरान उन्होंने खुद को सुरक्षित दिखाने के लिए खिलौने की पिस्टल का इस्तेमाल किया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला और उसके साथी ने एक स्थानीय ज्वेलरी दुकान का निशाना बनाया। दुकान में प्रवेश करते ही उन्होंने बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपाई और कर्मचारी पर खिलौने की पिस्टल तानकर ज्वेलरी लूट ली। घटना के समय दुकान में कुछ ग्राहक भी मौजूद थे, जो डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। दुकान मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अयोध्या पुलिस की विशेष टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।जांच में सामने आया कि लूट करने वाली महिला हिंदू धर्म की अनुयायी है और गर्भवती होने के बावजूद अपराध में शामिल थी। पुलिस ने बताया कि महिला और उसका बॉयफ्रेंड लूट की योजना पहले से बना रहे थे। दोनों ने घटना की वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है।पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह मामला समाज में सुरक्षा के प्रति चेतावनी है। किसी भी प्रकार की पहचान या धर्म को देखते हुए किसी को अपराध से अलग नहीं किया जा सकता। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

योगी सरकार का बड़ा कदम
पुलिस बल को मजबूत करने के लिए नई भर्तियां

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें रोजगार पाने और प्रदेश की सुरक्षा में योगदान देने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी भर्ती प्रक्रिया समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भर्ती प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल की ताकत बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को चुना जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ शामिल हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार पहले भी पुलिस प्रशिक्षण, वेतन और सुविधाओं में सुधार कर चुकी है। इस भर्ती के बाद पुलिस बल की संख्या और क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए भी विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि प्रदेश की सेवा का अवसर भी है।इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में 81,000 पदों पर भर्ती का निर्णय युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश की कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सादाबाद में हनुमान जी की भव्य शोभायात्रा,
जिला पंचायत अध्यक्ष ने विधिवत पूजा-अर्चना

सादाबाद में हनुमान जी महाराज की भव्य एवं ऐतिहासिक शोभायात्रा पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई, जिसने पूरे नगर को भक्तिमय रंग में रंग दिया। इस विशाल धार्मिक आयोजन का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा रामवीर उपाध्याय ने विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती कर किया। आरती के साथ ही वातावरण "जय श्री राम" और "जय बजरंगबली" के गगनभेदी नारों से गूंज उठा।शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आकर्षक झांकियों में भगवान हनुमान जी के विभिन्न रूपों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और भक्ति संगीत की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती शोभायात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया, जहां श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई और जलपान की उत्तम व्यवस्था की गईइस अवसर पर सीमा रामवीर उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान हनुमान जी शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। उनके आदर्श हमें जीवन में सत्य, सेवा और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान हैं। उन्होंने आयोजन समिति एवं सभी सहयोगियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। शोभायात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं व्यापार मंडलों द्वारा स्वागत द्वार और मंच लगाए गए, जिससे आयोजन की भव्यता और भी बढ़ गई। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस भव्य शोभायात्रा ने न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट किया, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का भी संदेश दिया, जिससे यह आयोजन सादाबाद के इतिहास में एक यादगार क्षण बन गया।